

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2023 TED

जहां था कभी बसों का रेला, जल्द होगा वहां हरियाली का बसेरा

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

दिल्ली में यमुना के किनारे जहां कभी बसों का रेला लगता था, जल्द ही वहां हरियाली का बसेरा होने वाला है। यहां ईको टूरिज्म का एक ऐसा माडल विकसित किया जाएगा जो यमुना के किनारे सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ इसके पुनर्विकास में भी सहायक होगा। मिलेनियम बस डिपो की करीब 62 एकड़ जमीन आखिरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को वापस मिल गई है।

जानकारी के मुताबिक, 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान डीडीए ने दिल्ली की तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार को यह जमीन अस्थायी तौर पर लो फ्लोर बसों का रखरखाव करने के लिए दी थी। बाद में यहां मिलेनियम बस डिपो बना दिया गया और करीब एक हजार बसें खड़ी की जाने लगीं। जब यहां प्रदूषण फैलने लगा और यमुना को भी नुकसान



पहुंचने लगा तो एक पर्यावरण कार्यकर्ता इस मामले को अदालत में ले गए। एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने यमुना की सफाई पर निगरानी के लिए गठित समिति से इस पर रिपोर्ट मांगी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) से इस बस डिपो को पर्यावरण के लिहाज से असुरक्षित बताते हुए यमुना किनारे

से इसे स्थानांतरित करने को कहा। एनजीटी के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ सदस्य बीएस सजवान व दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा की समिति ने एनजीटी को बताया कि डीटीसी बिना आवश्यक अनुमति हासिल किए इसका संचालन कर रहा है। अपशिष्ट जल भी नदी में छोड़ रहा है। एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने यह भी

कहा था कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के मुताबिक यहां पर इस्तेमाल किए गए इंजन आयल, अन्य आयल और ग्रीस जैसे खतरनाक पदार्थ भी निकलते हैं जो यमुना में ही बहा दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने इस बस डिपो को बनाए रखने की कोशिश लेकिन निर्णय डीडीए के पक्ष में गया। डीडीए के प्रमुख आयुक्त (उद्यान) राजीव

यह सही है कि हमें मिलेनियम बस डिपो वाली 62-63 एकड़ जमीन वापस मिल गई है। इसके पुनर्विकास के लिए कई प्रस्तावों पर बात चल रही है। जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इतना तय है कि जो भी प्रोजेक्ट फाइनल होगा, वह यहां हरित क्षेत्र के विकास और यमुना के पुनर्विकास को भी गति देने वाला होगा।

सुभाशीष पांडा, उपाध्यक्ष, डीडीए

- दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली सरकार से अंततः वापस मिली यमुना किनारे करीब 62 एकड़ जमीन
- राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान सरकार को अस्थायी तौर पर दी गई जमीन बना दिया गया था मिलेनियम डिपो

◀ मिलेनियम बस डिपो • जागरण आर्काइव

कुमार तिवारी ने बताया कि लंबी प्रक्रिया के बाद अब अंततः डीडीए को मिलेनियम बस डिपो की जमीन वापस मिल गई है। अब इसके पुनर्विकास की योजना पर विचार-विमर्श चल रहा है। उम्मीद है कि अब इस जमीन पर जो भी काम होगा, वह हरियाली से जुड़ा और पर्यावरण अनुकूल ही होगा। इसके पर्यावरण को फायदा होगा।

दिल्ली से बाहर प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली में काटे जाने वाले पेड़ों के प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए अब दिल्ली से बाहर एनसीआर व अन्य जिलों में जगह दी जाएगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पत्र का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए एजेंसियों को सीधे मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। मंत्रालय द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जगह दी जाएगी।

प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए डीडीए एक वर्ष पूर्व ही जमीन उपलब्ध कराने में असमर्थता

- परियोजनाओं के लिए काटे जाने वाले पेड़ों के लिए बदले नियम

- पेड़ काटने वाली एजेंसी को मंत्रालय के पोर्टल पर करना होगा आवेदन

जता चुका है। तत्कालीन डीडीए उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव को पत्र लिखा गया था। जमीन की कमी होने के कारण द फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। जमीन के जो छोटे टुकड़े बचे हैं, वे विकास व अन्य जरूरतों के लिए हैं। सन 1990 के बाद से दिल्ली में कोई भू-अधिग्रहण

नहीं हुआ है। द फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नियमों में बदलाव जरूरी है। दिल्ली राज्य नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र है। अतः प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए दिल्ली को अन्य राज्यों में जगह दी जा सकती है। मंत्रालय ने डीडीए के उक्त पत्र को फारेस्ट एग्जल कमेटी को सौंप दिया। कमेटी ने इसके तमाम पहलुओं पर विचार कर अपनी अनापति दे दी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों में खाली पड़ी

जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। एजेंसियों को मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वहां से हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के एनसीआर जिलों में जगह आवंटित की जाएगी। हालांकि दिल्ली वन विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार यमुना के डूब क्षेत्र की 9,000 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक पौधारोपण किया जा सकता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

DATED

THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, JANUARY 28, 2023

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शनिवार, 28 जनवरी 2023

Duping of JNU profs is latest example of land pooling fraud

ARNABJIT SUR
NEW DELHI, JANUARY 27

DAYS AFTER a case was lodged by the Delhi Police on the complaint of several JNU professors who have allegedly been duped of crores by a former employee of the university on the pretext of providing them flats, senior officers said that despite advertisements asking persons to not fall for such fraud schemes, such cases still persist.

A senior officer from the Economic Offences Wing (EOW) of Delhi Police said: "There are two types of land pooling scams — one where a person known to the victim carries out the fraud and one where the accused is unknown. The one including a known person is reported the most. Fraud cases involving land pooling scams spiked after it was notified for the second time in 2018 but it has considerably reduced in recent years."

The officer said that the Delhi Police had last month carried out a campaign on social media and put out advertisements regarding such frauds. "The targets of such scams mostly include government officers or bureaucrats who have the potential to invest in such housing schemes... The fraud revolves around the trust factor and the closer the victim is to the accused, the easier it becomes for the latter to cheat the victim and convince him to invest in the scheme. Victims often don't verify credentials of the accused person or his firm or society before investing in a scheme," another officer said.

Earlier this month, a case was lodged against one Dr P D Gaikwad, President of the Noble Socio-Scientific Welfare

Organisation (NSSWO) and also a former employee of the Jawaharlal Nehru University (JNU). According to the FIR in the case, he formed NSSWO in 2015 on the pretext of providing affordable housing in the Dwarka-Najafgarh area under the DDA's Land Pooling Policy of 2021.

The FIR read: "He approached professors of JNU, IIT and scientists of nearby institutes... the 10 complainants trusted him as he was a former employee of the university... after 7 years, he did not deliver anything even after taking timely installments. It appears now that NSSWO is fake and created for cheating. He promised to deliver the property within three years and collected installments."

The FIR further stated that after collecting the amount from all members, he allegedly stopped communicating with them and blocked their numbers. The complainants claimed that they lost crores of rupees after investing in the scheme, the FIR added.

Senior police officials privy to the probe said they are collecting the relevant documents pertaining to the investigation and are verifying the allegations.

A senior DDA official said that while initially meant to provide well-planned houses across Delhi-NCR, "the scheme can easily be manipulated by several individuals, builders and promoters alike by forming a fraudulent firm and inviting people to invest in a fake land".

Vijay Shankar Patel, PRO, DDA, said: "Intensive campaigns are carried out through media, informing people to not fall for such frauds and only seek information regarding any land pooling scheme from the official website of DDA."

नेबरहुड पार्क हुआ साफ

■ एनबीटी न्यूज़, नारायणा : नारायणा इलाके में बना नेबरहुड पार्क अब साफ हो गया है। सात जनवरी को एनबीटी में खबर छपने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया और यहां सफाई कराई गई। वहीं ओपन जिम की मशीनें अभी भी टूटी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे भी जल्द ठीक करा दी जाएंगी। वहीं लोगों ने एनबीटी का धन्यवाद किया।

पार्क के अंदर चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। लोगों की सुविधा के लिए पार्क में बनाए गए ओपन जिम की मशीनें भी टूट रही हैं। लोगों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी।

नारायणा में रहने वाले देवेंद्र तंवर, जीवन और आदित्य ने पार्क की दिक्कतों को लेकर एनबीटी को जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि डीडीए का यह पार्क नारायणा विहार और नारायणा गांव के बीच में पड़ता है। गंदगी के कारण बहुत से लोगों ने पार्क में आना भी बंद कर दिया है। इसके बाद सात जनवरी को पार्क की समस्या की खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई। खबर छपने के कुछ दिन बाद ही संबंधित विभाग ने एक्शन लिया। पार्क से कूड़ा उठाया गया और साफ-सफाई कराई गई।



सफाई होने के बाद यहां आने वाले लोगों को मिली राहत

Kejriwal announces 10-year plan for road repair and maintenance

Paras.Singh

paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi chief minister Arvind Kejriwal on Saturday announced a ten-year mega road repair and maintenance plan in a massive push to several ongoing road beautification projects across the city, underlining state government's focus on sprucing up public infrastructure in national capital.

According to the plan that the chief minister announced at a press conference, the state government will spend Rs 4,500 crore in the next one year on repair and maintenance of major streets, road furniture, foot over-bridges, subways, green patches and regular washing of the capital's roads. The government will spend Rs2000 crore each subsequent year on the programme, Kejriwal said.

He said that the plan also involves hiring of over 100 mechanical road sweeping machines, 150 tankers and sprinklers and 250 anti smog guns-cum-sprinklers which will be deployed for regular washing and sweeping of roads.

The maintenance work will include de-silting (twice a year) of drains, steps to prevent waterlogging, replacing damaged trees fused lights as well as coordinating with all civic bodies. The project also includes setting up of a control room to monitor day-to-day activities and progress at all levels.

Giving the timeline of the project, Kejriwal said that the state cabinet is expected to grant approval to a series of projects in the next ten days. He added that work orders are expected to be issued by March 20, and actual work on the ground may begin from April 1, 2023. The agencies will first take up the 1400 km roads that are maintained by the Public Works Department. All of these streets are wider than 18 metres. Narrower streets are maintained by Municipal Corporation of Delhi.

"All the footpath and central verges on these roads will be repaired: All broken manhole covers, pre-cast slabs, damaged poles and signages will also be repaired. All subways, railings, electrical fixtures, pedestrian bridges and street furniture will be maintained, and potholes and cracks on road surface will be cleared. We will complete the repair work in six months. Once the repair work is complete, we will issue a 10-year maintenance contract so that anything that is damaged will be immediately repaired within 24 hours of a complaint, so that streets look squeaky clean," Kejriwal said.



THE MEGA ROAD PLAN

₹4,500cr

Money to be spent in the next one year

₹2,000cr

Funds to be spent every subsequent year

10 days Time for Cabinet to clear project

March 20: Work order to be issued

April 1: Work expected to begin

WHAT WILL BE DONE?

- Widespread repair of the 1,400km roads under PWD, FOBs, central verges, subways, poles, streetlights, railings and street furniture
- 10-year maintenance contract to private agencies for further upkeep
- 24-hour limit for agencies to address demand for repair
- All roads to be re-carpeted twice in the 10-year contract period
- Road markings to be redone in 3-6 months cycle
- Street furniture to be repaired within 24 hours of wear and tear complaint
- 10-year contract for maintenance of green patches along the roads
- 100 mechanical road sweepers, 150 tankers and sprinklers and 250 anti-smog guns to be hired for cleaning roads
- Streets to be washed and scrubbed thrice a week, footpaths to be washed daily
- 10,000 kilolitres of treated water to be sourced daily from STPs

He added that the maintenance provision will also involve repair of potholes within 24 hours. "Streets will be resurfaced twice during the 10-year contract period. We see that the road markings, footpath, zebra crossing fade away, so they will be repainted in a 3-6 months cycle," he added.

The Public Works Department (PWD) is already implementing a separate road beautification project, in which new pavements are being constructed and road furniture is being installed across arterial stretches in the city.

Washing the roads

The government also plans to engage agencies for scrubbing and cleaning city's streets. "Under this contract, roads will be washed thrice a week and footpaths will be cleaned daily. We will also hire mechanical sweeping machines. The clean up will

also involve washing of the shrubs and trees along the streets," the chief minister said.

"150 water tankers and sprinklers will be hired for washing the roads, and another 250 anti-smog guns-cum-sprinklers will be hired for washing streets and trees on colony streets," he added.

The chief minister said that treated waste water from waste treatment plants will be used for washing roads. He added that besides removing illegal posters, banners on roadsides, green pockets will be made on central verges. "It will be 10-year contract under which plantation, trimming, washing, watering, putting manure and maintenance of good soil will be covered," he added.

Monitoring dashboards

The state government will deploy a third party monitoring system with dashboards and vehicle mounted cameras to keep a check

on the implementation of works listed by the government. "Third party independent monitoring will be carried out. We will have vehicle mounted with cameras which will be roaming across Delhi and capture images of works being done. All this will be monitored on a dashboard. The contract will also have the provision of levying heavy penalties if the work is found unsatisfactory," Kejriwal said. He added that a system will be put in place for citizens to lodge complaints.

S Velmurugan, chief scientist at Central Road Research Institute (CRRI), said it seems to be a unique model. "The arterial 1400 km of roads carry 70% of traffic and I don't think any other government has attempted something on this scale. The idea seems to be good but its efficacy will depend on implementation, monitoring and compliance," he said.

E-scooter sharing plan to take off from Dwarka: CM

Paras Singh

paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi government will soon launch an e-scooter sharing system in Dwarka sub-city in which 1,500 e-scooters will be deployed at 250 high footfall locations such as Metro stations, bus depots, markets, malls and educational institutions, in an effort to ensure last mile connectivity for commuters.

The e-scooters will be able to travel 60km in one charge at a maximum speed of 60kmph, and commuters will be able to travel in them using integrated tickets, which they will also be able to use to travel in buses and Metro, said Delhi chief minister Arvind Kejriwal in a press conference on Saturday.

"To ensure last mile connectivity and safety, we are undertaking this pilot project in Dwarka, which has 10 Metro stations and many bus stops. We will deploy 1,500 e-scooters at 250 location that will be accessible using integrated tickets. A person will be able to take a scooter from any of these locations, he or she will be provided a helmet and the e-scooters can be taken away, used and deposited at another of these 250 locations," said Kejriwal.

The government will soon call for open tenders to select the company that will provide and maintain the e-scooters. "Once the agreement is signed on a tender basis, 500 e-scooters will be deployed at 100 locations in the first four months. Another 500 scooters will be deployed in the 100 more locations in the next four months and finally, all 1,500 scooters will be put in place in 12 months," Kejriwal said.

The government will award the contract for seven years. "The bid parameter will be the minimum charge for ticket. We will select the company that will offer the tickets to users at the minimum rate," added Kejriwal. Once the experiment is successful, it will be replicated in other parts of the city.

Kejriwal said Delhi now has 7,500 buses and ensuring last

Dwarka electric scooter project

250 Locations	PHASED DEPLOYMENT
1500 e-scooters	FIRST 4 MONTHS
60 km per charge	100 locations 500 scooters
60 kmph	8 MONTHS
	200 locations 1,000 scooters
	12 MONTHS
	250 locations 1,500 scooters
	7 YEAR CONTRACT WILL BE ISSUED
	company offering lowest ticket price will be selected

mile connectivity will also reduce road traffic. "Once last mile connectivity is present, we can use carrot and stick policy and force people to use public transport. Once we have increased public participation in the public transport system, traffic will be reduced," he added.

Kejriwal said the public works department (PWD) is also working on removing traffic bottlenecks. "We have identified bottleneck points and PWD is working at each point with interventions like u-turns and flyovers. We are working on this plan," he added.

"The users will need a driving licence and they will need to be more than 18 years old. All the traffic rules will apply," he added.

An e-bicycle sharing project is currently in place in area under the New Delhi municipal corporation while bicycle sharing systems are being operated at select locations by the municipal corporation of Delhi.

The Delhi Development Authority tried to start a bicycle sharing project in Dwarka twice in the last five years but failed on both occasions. While the first tender floated by the authority failed to attract any company, the bidder who was awarded the contract during the second attempt did not execute the project.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2023

NAME OF NEWSPAPERS

यमुना की सफाई में प्रादेशिक सेना भी करेगी मदद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए अब प्रादेशिक सेना की भी मदद ली जाएगी। राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन (एनएमसीजी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को प्रादेशिक सेना की एक कंपनी प्रदान करने का फैसला लिया है। यह कंपनी उन सभी नालों और उप नालों की निगरानी सुनिश्चित करेगी जो सीधे यमुना में गिरते हैं। जनता को यमुना में गंदगी फेंकने से भी रोकेगी। एजेंसी ने यमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के किनारे एक बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित करने की इच्छा जताई है और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से इसके लिए जमीन मांगी है।

अधिकारियों के मुताबिक, एनएमसीजी ने यमुना में प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए इस

● राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रादेशिक सेना की एक कंपनी प्रदान करने का लिया निर्णय

● बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के किनारे एक बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित करने की भी इच्छा, दिल्ली विकास प्राधिकरण से मांगी जमीन

माह की शुरुआत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक में प्रादेशिक सेना की एक कंपनी (120 कर्मी) प्रदान करने की पेशकश की है। एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी पहली बैठक 20 जनवरी को की थी जब छह महीने की 'कार्ययोजना' तय की गई थी।

11 प्रमुख नालों का किया जाएगा आडिट: बैठक में (डीपीसीसी) द्वारा प्रस्तुत एक प्रेजेंटेशन के अनुसार, दिल्ली में यमुना में गिरने वाले 18 प्रमुख नालों में से सात ऐसे हैं जिन्हें अभी रोका नहीं जा सका है। इस दिशा में संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरा काम करने के लिए एक समयबद्ध रणनीति तैयार की गई है। इसी तरह नजफगढ़ नाले, शाहदरा नाले एवं सप्लीमेंट्री ट्रेन

में गिरने वाले करीब 70 उप नाले और कई छोटे-छोटे नाले हैं जिन्हें एजेंसियों द्वारा 2023 में बंद कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव और उच्च स्तरीय समिति के संयोजक नरेश कुमार ने कहा, "प्रादेशिक सेना की कंपनी दिल्ली जल बोर्ड सेप्टेज प्रबंधन विनियम 2018 भी लागू करेगी जो सेप्टिक टैंक कचरे के परिवहन और निपटान से संबंधित है। यह लोगों को नालियों में कचरा नहीं फेंकने के लिए भी समझाती है।" उच्च-स्तरीय समिति ने दिल्ली जल बोर्ड को फरवरी 2023 तक एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से 11 प्रमुख नालों और सभी उप नालों का प्रदर्शन आडिट भी करने के लिए कहा है जिनकी गंदगी अब यमुना में नहीं जा रही है। इस बीच जल बोर्ड, एमसीडी और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की

एक बहु विषयक टीम के अनुसार विभाग एक आंतरिक आडिट भी करेगा।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में वनेगा बायोडायवर्सिटी पार्क: अधिकारियों ने कहा कि समिति ने डीडीए को यमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भूमि चिह्नित करने तथा बायोडायवर्सिटी पार्क के विकास के लिए 15 फरवरी तक एनएमसीजी को आवंटित करने के लिए भी कहा है। राजस्व विभाग के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव (वन और पर्यावरण), डीडीए के उपाध्यक्ष और जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी आदेश के साथ भूमि संबंधी सभी मामलों को हल करने के लिए एक समिति भी बनाई गई है। कुमार ने इस संबंध में सभी हितधारकों के साथ साझा किए गए एक आदेश में आगे कहा, "समिति एक पखवाड़े के भीतर सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए जल बोर्ड और एनएमसीजी को आवश्यक भूमि पार्सल की पहचान और सौंपना सुनिश्चित करेगी।"

जनता को जागरूक करने को चलेगा शिक्षा अभियान

समिति ने दिल्ली सरकार के आइटी विभाग को एक पखवाड़े के भीतर ई-प्रगति डैशबोर्ड को चालू करने और निगरानी के उद्देश्य से उस पर कार्य योजना पोस्ट करने के लिए भी कहा है। साथ ही जलबोर्ड, डीपीसीसी, बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग तथा डीडीए को 'यमुना नदी के पुराने गौरव को बहाल करने की पहल' में जनता को शामिल करने के लिए एक सूचना और शिक्षा अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

NEW DELHI
SUNDAY
JANUARY 29, 2023

DATED

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
JANUARY 29, 2023

Prepare for LS '24, Delhi '25, BJP tells members at meet

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Union minister Anurag Thakur on Saturday said the Bharatiya Janata Party (BJP) must expose the corrupt Aam Aadmi Party government in Delhi, and work towards the BJP's victory in the Lok Sabha elections in 2024 and the Delhi assembly elections in 2025.

He was addressing party leaders at the BJP's state executive meeting in New Delhi on Saturday, at which the party passed a political resolution to expose the failures of the Delhi government.

The AAP did not comment on the matter.

Addressing the meeting, Thakur said, "I campaigned in many areas in the city during the Delhi municipal elections and found that people are no longer impressed by the Kejriwal government. This was reflected in the recent MCD election results where AAP won by a negligible majority. It is our resolution to take the development works being done by the Narendra Modi government in Delhi to the

public and ensure the party's victory in the Lok Sabha elections in 2024 and the 2025 assembly elections."

He added, "In the last eight years in Delhi, the Modi government has undertaken development projects worth more than ₹1 lakh crore for the city. Under the guidance of the central government, the Delhi Development Authority and the lieutenant governor are carrying out development work at the Yamuna riverfront. Due to the work being done by the lieutenant governor on the Najafgarh drain, it is now becoming a tourist attraction."

Delhi BJP working president Virendra Sachdeva told party workers that they should dedicate the next 400 days to organising regular public contact programmes to ensure "we win all seven seats in the Lok Sabha polls next year".

BJP MLA and leader of the opposition in the Delhi Assembly Ramvir Singh Bidhuri said, "The Kejriwal government is a corrupt government which is now completely cut off from the public and has cheated the people of Delhi."

Millennium bus depot land back, DDA plans to restore it

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority recently recovered around 60 acres used by Delhi Transport Corporation for the Millennium Bus Depot for many years. The land is located on the Yamuna floodplain and DDA is working on its restoration.

A DDA official said that the land has a blacktop since it was used for the parking of buses and the restoration, as such, will take time. "We have just got the land back. We will prepare a concept plan befitting the Yamuna floodplain, probably in line with other restoration projects underway on the Yamuna banks," the official said. On Saturday, TOI saw some plants being planted at the site.

Prior to the 2010 Commonwealth Games, a temporary depot was erected on the riverbank with parking space for around 1,000 buses. Other facilities, including five workshop-cum-scanning centres, a logistics centre and two CNG-filling stations, were also put up.

However, an environmentalist pleaded to the National Green Tribunal that the depot be shifted from the floodplain. NGT asked the petitioner to take the matter to the committee appointed by the green court to monitor the Yamuna's cleaning. The panel, which included retired NGT expert member B S Sajwan and former Delhi chief secretary Shailaja Chandra, informed the court that DTC had been operating without necessary approvals and discharging wastewater into the river. It recommended the shifting of the depot.

"Whatever we do at the site will be done keeping in mind the NGT order," said DDA vi-



Rajesh Mehta



As DTC had concretised the land for parking, its restoration will take time, says a DDA official

ce-chairman Subhasish Panda. The area is situated next to the Nizamuddin Bridge and behind IP Power Station.

In April 2019 the matter related to the bus depot was transferred to NGT by the Supreme Court on the grounds that there cannot be "parallel proceedings" on the same issue. It had earlier said that ordering demolition of the bus depot wouldn't be appropriate and had granted Delhi government and DTC one year to get the zoning parameters under Delhi Master Plan amended, failing which it would have to shift the depot.

The apex court also noted that Delhi High Court had

granted an opportunity to Delhi government and DTC in October 2015 to make the amendment in the Master Plan, if it was permissible in law, within six months. The state government and DTC had challenged the high court's decision dismissing the transporter's plea for six months to approach DDA to change the land use of the depot site. According to sources, DDA had submitted that land-use amendment was not possible as NGT had prohibited construction in areas demarcated as Zone O (river and waterbody areas) and the depot site fell in such a zone.

Manoj Misra, convenor of NGO Yamuna Jiye Abhiyan, said that the order to shift the depot and restore the land to DDA was welcomed. "Anand Arya, an environmentalist, and I have been pursuing the matter since 2013 and we even filed petitions in the Supreme Court and high court for restoration of the riverbank land," said Misra. "In 2011, the Delhi Urban Art Commission had advised that all structure from the bus depot should be removed and the floodplain be restored. I hope that the DDA will do as advised now."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS _____

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
JANUARY 29, 2023

DATED _____

Territorial Army staff to guard drains polluting Yamuna, make people aware

Atul Mathur &
Priyangi Agarwal | TNN

New Delhi: National Mission for Cleaning Ganga (NMCG) has decided to provide a company of Territorial Army to Delhi Pollution Control Committee, which will ensure monitoring of all drains and sub-drains that directly fall into the Yamuna and are yet to be trapped.

The agency has also expressed its desire to develop a biodiversity park along the Yamuna floodplain and sought land from Delhi Development Authority.

According to officials, the offer to provide a company (120 personnel) of the Territorial Army was made by NMCG in the first meeting of the high-level committee constituted by the national green tribunal earlier this month to deal with the issue of pollution in the Yamuna. The committee, chaired by lieutenant governor VK Saxena, had held its first meeting on January 20 when a six-month 'plan of action' had been decided.

As per a presentation made by Delhi Pollution Control Committee (DPCC) in the meeting, of the 18 major drains falling into the Yamuna in Delhi stretch, there are seven that are left from trapping

PLAN OF ACTION

100%
treatment of sewage
generated in the city

Gap in sewage
treatment now is
238MGD

STP DEADLINES

- > Okhla sewage treatment plant to be ready by June 2023
- > Sonia Vihar by Sept
- > Delhi Gate within 12 months

40 decentralised STPs planned – 29 by December, rest within 12 months of allotment of land

- > Rehabilitation of Kondli phase-II and Rithala phase-I by June, and Yamuna Vihar phase-II by September
- > Upgradation of 18 STPs by March 2024 and 13 common effluent treatment plants

Representative picture



MORE WORK

- > Drains to be desilted by September
- > Seven major drains to be trapped in 2023. All un-intercepted sub-drains falling into Najafgarh, supplementary and Shahdara drains to be trapped this year
- > Full trapping and treatment of 242MGD wastewater by June
- > Performance audit of

completely trapped 11 major drains and all sub-drains planned

- > Extending sewerage network in all 1,799 unauthorised colonies and 639 JJ clusters

- > Regulation of Yamuna floodplain, including removal of encroachments and dhobi ghats
- > Utilisation of treated STP water

and a detailed timeline has been prepared by the agencies to complete the work. Similarly, there are about 70 sub-drains and many unrecorded smaller drains that fall into the Najafgarh drain, Shahdara drain and Supplementary drain, which will be closed by the agencies in 2023.

"The company of Territorial Army would also enforce the Delhi Water Board Septage Management Regulations 2018, which deal with transportation and disposal of septic tank waste, apart from convincing people not to throw the waste in drains," chief secretary Naresh Kumar, who is also the convener of the committee, stated.

The high-level committee has also asked Delhi Jal Board to undertake a performance audit of completely trapped 11 major drains and all sub-drains through an independent agency by February 2023. Meanwhile, a multidisciplinary team of DJB, MCD and irrigation & flood control department will carry out an inter-

nal audit, said an official. Officials added that the committee has asked DDA to identify and allot a piece of land in the floodplain and allot it to NMCG by February 15 for the development of a biodiversity park. They further said that a committee has also been formed under the chairmanship of divisional commissioner of revenue department with principal secretary (forest and environment), DDA vice-chairman and DJB chief executive officer as members to resolve all land-related matters.

"The committee shall ensure identification and handing over the requisite land parcels to DJB, for setting up of sewage treatment plants, and to NMCG within a fortnight," Kumar further said.

The minutes of the meeting were shared with all stakeholders. The committee has also asked the IT department of Delhi government to operationalise e-Pragati dashboard within a fortnight and post the action plan on it for the purpose of monitoring. It also asked DJB, DPCC, I&F department and DDA to carry out an information and education campaign to involve the general public in the "initiative to restore the old glory of river Yamuna".

Cancer hospital violating land allotment norms: DDA to HC

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has informed the Delhi high court that land worth Rs 6.4 crore was allotted for Rs 71 lakh to Rajiv Gandhi Cancer Hospital. The submission was made through an affidavit filed in a plea that alleged that the hospital had breached the condition of free treatment to poor, which was imposed when the land was given to the hospital on concessional rates.

The plea was filed by Social Jurist, a civil rights group. It alleged that the hospital, which has 302 beds, has been in violation of the conditions of land allotment with regard to providing free treatment to patients belonging to the economically weaker section (EWS).

"The respondent hospital has made unwarranted profits during the last two decades by not providing at all free treatment to EWS patients, therefore, it is liable to make good to society by paying such an amount of unwarranted

profit to DDA in terms of an earlier decision of the high court," the petitioner stated.

According to the plea, the hospital is run by Indraprastha Cancer Society & Research Centre, to whom the public land was allotted by DDA for the construction of the hospital

The hospital breached the condition of free treatment to the poor, which was imposed when the land was given to it on concessional rates, the plea claimed

with a condition that they would provide free treatment to EWS patients to the extent of 10% indoor patient department and 25% outdoor patient department.

The affidavit further stated that in 1994, the hospital informed DDA that it would provide free treatment to 25% indoor and 40% outdoor patients. However, the hospital has violated the conditions, it alleged.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, JANUARY 30, 2023

Villages Shown A Dream, But Nothing Changes On Ground

Projects Stuck Amid Lack Of Coordination Among Agencies, Administrative Hurdles

Atul Mathur@timesgroup.com

New Delhi: Lack of coordination between various government agencies and administrative hurdles have led to a large number of infrastructure and welfare projects meant for the development of rural and urban villages of the capital getting stuck at various stages in the last four years.

According to an estimate, nearly 1,250 projects worth more than Rs 1,500 crore have been approved by Delhi Village Development Board (DVDB) since 2018, but only a handful have been executed till date.

All 357 rural and urban villages of Delhi fall under the jurisdiction of DVDB. It is the responsibility of the board to prepare the blueprint of infrastructure and welfare projects that are required in each of these villages to improve civic conditions, sanction money and forward it to various agencies for execution. These projects include repair and construction of village roads and drains, installation of streetlights, rejuvenation of parks, community centres and cremation grounds.

According to Centre for Youth, Culture, Law and Environment (CYCLE), an organisation working for the rights of farmers and development of Delhi's villages, of 936 projects worth Rs 1,258 crore that came up before DVDB till March 31, 2021, only 86 were approved. The board approved 303 more projects in 2021-22 and 2022-23, including 136 this week.

"Between 2018 and 2021, DVDB approved development projects of Rs 1,258 crore but work didn't start even on one of them. The work on 86 smaller projects of Rs 30 crore was started during this period but even that was left midway. In the last two financial years, projects worth Rs 265 crore were announced. The Delhi government had announced spending Rs 2 crore

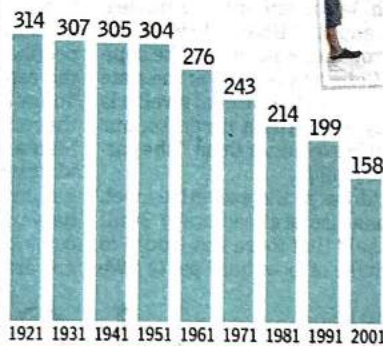


DEVELOPMENT YET TO TAKE OFF

➤ According to 2011 census, Delhi has 105 villages (urban & rural) and 113 census towns

➤ The city had 357 villages before 1911

NO. OF VILLAGES
As per census records



Work of over ₹1,500 crore approved by development board since 2018



Projects approved by development board



Repair and construction of roads and drains



Installing streetlights

Development of cremation grounds



Redevelopment of community centres



Rejuvenation of parks



₹793 crore lying in FDs not used by Delhi government for development of villages

per village per year in 2015. That means, it should have so far spent Rs 5,600 crore on the redevelopment of villages. But the reality is for everybody to see," said Paras Tyagi of CYCLE.

Villagers said they have made regular requests both to the Delhi government as well as DDA, but there has been no response. While no immediate reaction was available from the Delhi govern-

ment, a DDA official said the gram sabha land was taken over by the agency to fast track the development work. "We have now started the work in many villages," claimed an official.

But the villagers said many of these projects were stuck because of the lack of coordination between DDA and the Delhi government.

"Our village was urbanised

in February 2021 and the gram sabha land was taken over by DDA. The rejuvenation of a waterbody was to be started by the irrigation and flood control department, but it could not start because of encroachment on surrounding gram sabha land, which comes under DDA. Similarly, the work on a trash compactor was stopped by DDA midway," said Ritesh Rana, general

secretary, Bakhtawarpur Residential Welfare Society

Ansh Tanwar of Fatehpur Beri village said the village land taken over by the government was now under the control of the forest department. "The villagers used to have control over this land and even carried out various works. But now, we have to buy a ticket to even enter that part since it has been converted into a biodiversity park," Tanwar said.

Jitendar Yadav, a member of the RWA of Village Jhuljhuli, said they have been frequently requesting the development department of Delhi government for completion of various approved projects. "We recently wrote again to remind the government about installation of streetlights, fixing of high mast lights, construction of multipurpose hall and open gym. These projects have been approved but are pending," said Yadav.

According to Dr Rajbir Solanki of Delhi Mool Grameen Panchayat, the condition of community centres and cremation grounds is in a bad shape but the agencies don't listen to them. "Most rural villages have been declared urbanised but facilities such as libraries are not available. The IGL pipeline has been laid in the periphery but the villagers have not been provided the connections," he added.

Interestingly, the Delhi government has a corpus of almost Rs 800 crore (including interest), in the form of fixed deposits, which got transferred to it when the panchayat system was abolished in 1990-91 and the villages' money was transferred to the block development officers. "Even the Delhi Financial Commission had recommended that this money should be used for the development of villages. What is the use if the villagers' money is not used for the improvement of the villages," Tyagi said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS _____

DATED _____

04

NEW DELHI
MONDAY
JANUARY 30, 2023

Hindustan Times

DDA looks to rework its slum rehabilitation plan

Risha Chitlangia

Risha.chitlangia@htlive.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) is planning to revise its slum rehabilitation policy, nearly three months after Prime Minister Narendra Modi inaugurated DDA's first in-situ slum redevelopment project in south Delhi's Kalkaji where he gave residents of Bhoomiheen Camp the keys to their new flats.

Officials aware of the matter said the policy revision is being considered due to poor response from developers to other slum rehabilitation projects across the city.

"Despite efforts, we have not received a good response from developers. We will rework the policy to make it more attractive to developers," said a senior DDA official.

However, the slum redevelopment projects already in construction will not be impacted if DDA decides to change the policy, said officials. Only those projects on which construction has not yet begun will be impacted by the changes, officials added.

In the past two years, DDA invited bids for rehabilitation of 10 slum clusters, including Dilshad Garden, Shalimar Bagh, Rohini, Pooth Kalan, Haiderpur, Okhla Industrial area, Vasant Kunj and Kalkaji. DDA has prepared a plan to construct 22,352 flats in these 10 clusters. In 2021, DDA amended the norms for in-situ rehabilitation in a bid to make the projects financially

REHABILITATING SLUM RESIDENTS

DDA considering ways to make the slum redevelopment policy more financially viable and attractive for developers

10 IN-SITU PROJECTS TENDERED BY DDA

22,352 FLATS PROPOSED TO BE BUILT FOR REHABILITATION OF 10 SLUM CLUSTERS



LIST OF PROJECTS

- Dilshad Garden: 3,367 flats
- Shalimar Bagh-Pitampura: 1,116
- Suraj Park in Rohini: 2,566
- Badli, sector 19 Rohini: 984
- Rohini Extension, Pooth Kalan: 504
- Haiderpur: 1,800
- Indira Kalyan camp, Okhla Ph-1: 3,500
- Govindpuri, Kalkaji: 5,437
- Kusum Pahadi, Vasant Kunj: 2,808
- Majdoor Kalyan Camp, Okhla Industrial Area Ph-1 and 2: 670

ONGOING PROJECTS

- 1 Kalkaji Extension Phase-I: Completed
- 2 Kalkaji Extension phase-II: To start soon
- 3 Jailorwala Bagh: nearing completion
- 4 Kathputli Colony: to be completed by this year end

EARLIER AMENDMENTS TO THE POLICY

- In remunerative component, Floor Area Ratio (FAR) increased from 200 to 300
- Arrangement for residents in transit camps or payment of ₹6,000 per month per beneficiary
- Developer allowed to decide on type of project (either residential or commercial)

viable.

Of the 675 identified slum clusters in Delhi, 376 are on central government-owned land parcels and DDA is the nodal agency for the rehabilitation of these clusters.

According to DDA policy, a developer will have to construct flats for economically weaker sections and then will be able to recover the project cost through the remunerative component, which is 40% of the total area.

"We have twice invited bids

for these projects. Last year, some developers showed interest but they asked us for financial assistance up to ₹100-200 crore. It is not possible for the government to pay developers. We have to look for alternatives so that developers can recover the project cost," said the official.

These 10 projects will be developed on a public private partnership model. The second phase of the slum redevelopment at Kalkaji Extension,

which involves Navjeevan Camp and Jawahar Lal Camp slum clusters, will also follow PPP model, said officials.

Meanwhile, more than 10 beneficiaries at Bhoomiheen camp, who were given keys to their new flats by Prime Minister Narendra Modi at a function in November, have shifted to the new 13-storeyed housing complex, while more than 750 families of the 1,862 beneficiaries have taken physical possession of their flats, according to DDA.

पहले भी मिले हैं सड़कों और फ्लाईओवरों को नए नाम

मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करने के बाद फिर शुरू हुई बहस

Prashant.Soni@timesgroup.com

■ नई दिल्ली: राष्ट्रपति भवन के मशहूर 'मुगल गार्डन' का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' रखे जाने से पहले भी दिल्ली में कई सड़कों और फ्लाईओवरों के नाम बदले गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 5-7 साल के दौरान दिल्ली की दर्जन भर से ज्यादा सड़कों के नाम बदले जा चुके हैं। अक्सर नाम बदलने पर विवाद भी होते रहे हैं। वहीं राजनैतिक पार्टियां और संगठन भी अक्सर स्मारकों और सड़कों के नाम बदलने को लेकर मांग करते रहे हैं। पिछले साल ही डीडीए के 16 पार्कों का नामकरण भी गुप्तनाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया गया था। इसके अलावा दिल्ली के 40 अन्य गांवों के नाम बदलने का प्रस्ताव भी बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार को भेजा गया था।

कई सड़कों के बदले गए नाम

सड़कों के नाम बदलने में सबसे ताजा उदाहरण कर्तव्य पथ का है, जिसे लोग राजपथ के नाम से जानते थे। 2019 में दिल्ली सरकार ने मुकरबा चौक का नामकरण कार्गिल वॉर के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बतरा के नाम पर किया था। महारौली-बदरपुर रोड का नाम भी आचार्य महाप्रज्ञ मार्ग किया गया। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदलकर सुप्रीम कोर्ट किया गया। सबसे ज्यादा बदलाव नई दिल्ली की सड़कों पर ही देखने को मिल है। 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग किया गया। वहीं, 2016 में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर वाली रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था। 2017 में डलहौजी रोड का नाम भी बदलकर दाराशिकोह रोड किया गया, जबकि 2018 में तीन मूर्ति चौक के नाम में बदलाव करके इसे तीन मूर्ति हाइफा चौक का नया नाम दिया गया।

पिछले साल दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर तुगलक रोड का नाम गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब लेन का नाम अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन सिंह रावत रोड रखने की मांग की थी। उससे पहले 2020 में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने भी बंगाली मार्केट से जुड़ी बाबर रोड का नाम बदलकर 5 अगस्त मार्ग रखने का प्रस्ताव रखा था। तब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का शिलान्यास करने वाले थे।

फ्लाईओवर-पार्कों के नाम भी बदले

दिल्ली में फ्लाईओवरों के भी नाम बदले गए हैं। मसलन, 2016 में दिल्ली सरकार ने बारापूला एलिफेंट रोड का नाम बदलकर बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु रखा, तो वहीं लाजपत नगर फ्लाईओवर का नाम झुलेलाल सेतु



कागजों या साइनेज पर नाम बदल देने के बाद भी आम लोग नए नामों के साथ नहीं बना पाते हैं अपना जुड़ाव

पुराने नाम भूल नहीं पाते लोग

- कर्नाट प्लेस का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर 'राजीव चौक' कर दिया था, पर लोग आज भी सीपी के नाम से ज्यादा जानते हैं
- दिल्ली के 40 अन्य गांवों के नाम बदलने का प्रस्ताव भी बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार को भेजा गया था
- पिछले साल डीडीए के 16 पार्कों का नामकरण भी गुप्तनाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया गया था

रखा गया। पिछले साल डीडीए के 16 पार्कों का नामकरण भी गुप्तनाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया गया था। 2019 में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। वहीं, पिछले साल एमसीडी ने साउथ दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस से सटे मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया था। दिल्ली के 40 अन्य गांवों के नाम बदलने का प्रस्ताव भी बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार को भेजा गया था।

राजधानी दिल्ली का नाम भी बदलने की हो चुकी है मांग

दिल्ली की सड़कों और जगहों का नहीं बल्कि दिल्ली शहर का नाम बदलने की मांग भी समय-समय पर उठती रही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और संत महासभा ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखने की मांग की थी।

नाम जो बदले गए

- कर्नाट प्लेस : राजीव चौक
- मुगल गार्डन : अमृत उद्यान
- राजपथ : कर्तव्य पथ
- महारौली-बदरपुर रोड : आचार्य महाप्रज्ञ मार्ग
- रेस कोर्स रोड : लोक कल्याण मार्ग
- डलहौजी रोड : दाराशिकोह रोड
- तीन मूर्ति चौक : तीन मूर्ति हाइफा चौक
- लाजपत नगर फ्लाईओवर : झुलेलाल सेतु
- मोहम्मदपुर गांव : माधवपुरम
- फिरोजशाह कोटला स्टेडियम : अरुण जेटली स्टेडियम
- बारापूला एलिफेंट रोड : बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु
- औरंगजेब रोड : डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग
- प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन : सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन
- मुकरबा चौक : शहीद कैप्टन विक्रम बतरा चौक

ये हैं प्रस्ताव

- दिल्ली : इंद्रप्रस्थ
- तुगलक रोड : गुरु गोबिंद सिंह मार्ग
- अकबर रोड : महाराणा प्रताप रोड
- औरंगजेब लेन : अब्दुल कलाम लेन
- हुमायूं रोड : महर्षि वाल्मीकि रोड
- शाहजहां रोड : जनरल बिपिन सिंह रावत रोड
- बाबर रोड : 5 अगस्त मार्ग

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | सोमवार, 30 जनवरी 2023

DATED

सागरपुर : ज़ब्त गाड़ियों की सुरक्षा के नहीं कोई इंतज़ाम, चोरी हो रहे पाटर्स

■ अश्वनी शर्मा, सागरपुर

सागरपुर इलाके में मौजूद डीडीए पार्क को लंबे समय से दिल्ली पुलिस ने ज़ब्त की जाने वाली गाड़ियों का ठिकाना बनाया हुआ है, लेकिन पिछले काफी समय से इस जगह की देखभाल नहीं होने की वजह से अब स्थानीय लोगों को इस जगह को आसामाजिक तत्वों की तरफ से निशाना बनाने का डर सता रहा है।

दरअसल यहां मौजूद ज़ब्त गाड़ियों से सामान चोरी होना आम बात हो गया है। ऐसे में यह आशंका है कि वे यहां मौजूद गाड़ियों से नंबर प्लेट चुराकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। हद तो यह है कि स्थानीय लोगों के बार-बार इस तरफ ध्यान दिलाने के बाद भी दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सागरपुर में रहने वाले राजकुमार ने बताया कि सागरपुर स्थित राजीव पार्क-कमल पार्क के ठीक सामने डीडीए का यह पार्क है। यह पार्क काफी बड़ा है। पुलिस ने डीडीए



इस जगह की देखभाल नहीं होने की वजह से बढ़ी दिक्कत

की जमीन के कुछ हिस्सों को लीज पर ले रखा है। यहां उन्होंने ज़ब्त की गई गाड़ियों को रखा हुआ है। यह गाड़ियां लंबे समय से पड़ी हुई हैं। यहां दो बार आग भी लग चुकी है। आग लगने के बाद पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई थी और पार्क में लोगों का आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन अब भी यहां कोई भी आ जा सकता है। पार्क में बैठे बुजुर्ग टीका राम और



मनोज अहिरवाल ने बताया कि डीडीए पार्क में काफी समय से गाड़ियां पड़ी हुई हैं। कई गाड़ियों के पार्ट भी गायब हैं। शिव कुमार का आरोप है कि अगर पुलिस ने किसी चीज को ज़ब्त किया है तो उसकी सुरक्षा पुलिसकर्मियों को करनी चाहिए।

हिन्दुस्तान

सोमवार
30 जनवरी 2023

द्वारका में खेल हब बनाने की तैयारी

■ सज्जन चौधरी

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से द्वारका को उत्तर भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। डीडीए की ओर से द्वारका के अलग-अलग सेक्टरों में 8 से अधिक खेल परिसर (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स) बनाए जा रहे हैं।

मौजूदा वर्ष में डीडीए की ओर से द्वारका में 4 नए खेल परिसर तैयार किए जा रहे हैं। जून तक द्वारका के सेक्टर-17 में खेल परिसर जनता को समर्पित करने की तैयारी है।

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इनमें सभी विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाया जाए। इसके



दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकसित करेगा

04 नए परिसर द्वारका
में बनाए जा रहे हैं

अतिरिक्त, डीडीए द्वारका में ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाने जा रहा है, जिसका अभी काम शुरू होना शेष है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये सभी खेल परिसर तय समयसीमा के अनुसार तैयार हो जाएंगे और इनका जल्द दिल्ली के लोगों को लाभ

यहां हो रहा है निर्माण

स्थान	मूँमि	लागत
द्वारका सेक्टर-17	23.7	41
द्वारका सेक्टर-23	17.5	16.3
द्वारका सेक्टर-8	23.3	19
द्वारका सेक्टर 19	19.9	22
द्वारका सेक्टर 19बी	52	250
द्वारका सेक्टर 33	22	27.3

(नोट : मूँमि एकड़ में है और लागत करोड़ में है)

मिलना शुरू हो जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि नए बनाए जा रहे खेल परिसरों में ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, जिससे एक ही स्थान पर कई खेलों के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। पुराने खेल परिसर में भी खेल संबंधी सुविधाओं को समय-समय पर अपग्रेड किया जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEW

पंजाब केसरी

DELHI

28 जनवरी, 2023 ▶ शनिवार

---DATED---

तुगलकाबाद किला में कब्जे हटाने की मियाद आज तक

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राजधानी के तुगलकाबाद किला के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने संरक्षित क्षेत्र में बने अवैध घरों को हटाने

के लिए नोटिस चस्पा किए थे। ऐसे में अभी तक किसी भी अतिक्रमण के

खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती नजर नहीं

आई है। एएसआई द्वारा नोटिस के अनुसार इसे 28

जनवरी तक खाली करना था।

अब नोटिस के अनुसार इसकी समय सीमा भी खत्म होने वाली है।

जिससे एएसआई इस मामले को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। एएसआई ने

इसे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)

समेत विभिन्न एजेंसियों को दे दिया था। इस अभियान के जरिए एक हजार से

अधिक अवैध घरों के बाहर घर खाली करने का नोटिस चस्पा किए थे। जिसमें

इन लोगों से 15 दिन के भीतर घर खाली करने का आदेश दिया था। बता दें यह

कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 24 नवंबर को अतिक्रमण हटाने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई को अंतिम निवेदन के रूप में छह सप्ताह का समय दिए जाने के बाद आई है।

एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी

ने बताया कि इस मामले को

स्थानीय प्रशासन को दिया

गया है। उन्होंने इसे लेकर

नोटिस पहले ही दिया था।

अब आगे की कार्रवाई

सिविक एजेंसियां करेंगी।

एएसआई के दिल्ली सर्किल के

सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण

सिंह ने बताया कि यह मामला सन

1995 का है। दिल्ली विकास

प्राधिकरण (डीडीए) ने भूमि और

विकास कार्यालय द्वारा देखभाल और

रखरखाव के उद्देश्य से 2,661 बीघा

का क्षेत्र एएसआई को सौंप दिया गया

था। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में

50 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र पर अवैध

रूप से लोगों का कब्जा है। अब तक

अतिक्रमणकारियों के घरों की दीवारों

पर 1000 से ज्यादा नोटिस चिपकाए

जा चुके हैं।

एएसआई
ने एक हजार से
अधिक अवैध निर्माण
पर चस्पा किए थे
नोटिस

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

 the pioneer

NEW DELHI | MONDAY | JANUARY 30, 2023 PERS DATED

Setting up of CCTV cameras sought in area outside JNU

STAFF REPORTER ■
NEW DELHI

Protests at the Jawaharlal Nehru University (JNU) have started troubling senior citizens living in Delhi's Munirka Vihar, not for the noise or the traffic but strangers knocking on their doors to use the washrooms.

The lack of public convenience booths in the locality has also resulted in people relieving themselves in the open, causing a foul smell in the entire area, local residents said, claiming that they have approached authorities on sev-



eral occasions but in vain.

The Senior Citizen Forum of the locality has now written to Prime Minister Narendra Modi highlighting the issue,

demanding the construction of a public convenience booth to avoid open defecation on Bada Gang Nath Marg near Rock Garden, Munirka, and also the installation of CCTV cameras for security reasons.

In the letter dated December 12, 2022, the forum noted that the DDA flats in Munirka Vihar were mostly allotted to central government employees in 1977 and most of the residents now are senior citizens.

The situation worsens during protests at the university, which is located just opposite Munirka Vihar, locals claimed.

As there is no public convenience booth, police personnel and media persons stationed outside the university often knock on the doors of the people living there while some relieve themselves in the open, they alleged, adding that residents are also concerned about the health impact of the open defecation.

Forum member P N Malhotra said the concerns had been raised several times but nothing was ever done to address them. Due to the lack of convenience booths, women police personnel and media persons face major problems.

"Men can relieve themselves in open. Let me stress that this is also wrong. But when there are no other option, they can. But women journalists stationed outside the university for hours have no option but to knock on our doors," he said.

"We try to help them, but we also feel unsafe because the security situation outside is not great. It is necessary to instal CCTV cameras in the area and build a convenience booth," Malhotra added.

Another resident, K C Pathak, also highlighted the issue and said a well-maintained public convenience

booth for police personnel and media persons needs to be built outside the JNU gate as the protest often continue for many days.

Besides, the facility will also come to the use of passers-by as there is no other public convenience booth in the area, she said. Protests at JNU and deployment of police personnel have become an usual phenomenon, causing inconvenience to residents of the locality, especially when traffic is diverted.

Stressing on the need for CCTV surveillance, resident Satwant Kaur said it was very

much required as many residents in the area are senior citizens and some even live alone. "Their houses are prone to theft and burglary," she said, adding, "CCTV surveillance would instill fear in the minds of outlaws."

In the letter to the prime minister, the Senior Citizen Forum wrote, "Our police force in Delhi works day and night to safeguard the security of our worthy VIPs, senior citizens and residents of Delhi."

Our police force deserves your appreciation and reward of encouragement to boost their efficiency. The letter also

mentioned other demands of the people in the locality such as covering open drains and verification of vendors.

It asked for 'installation of a small LED screen' in the police booth near D Street gate of DDA flats, Munirka, and 85 CCTV cameras in D, E, F and G blocks.

There should be "verification of vendors, domestic helps, car cleaners etc. In our colony. Marking for parking of cars in our colony to provide way for ambulances and fire tenders. Construction of broken wall in D street," the forum said in the letter.

 sunday pioneer
NEW DELHI | SUNDAY | JANUARY 29, 2023

Orders issued, tasks outlined for cleaning, rejuvenating Yamuna

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The High Level Committee (HLC) headed by Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena, constituted by the National Green Tribunal (NGT), issued detailed orders with specific tasks and timelines to ensure the cleaning/rejuvenation of river Yamuna and the sewage carrying drains falling into it.

All the crucial parameters on river health [like BOD < 3 mg/l, DO > 5 mg/l, minimum environmental flow — 23 Cumecs (437 MGD), etc.] were accepted by the HLC, and to achieve these parameters, the HLC finalized the Action Plan, including but not limiting to

treatment of all sewage generated in Delhi, trapping of all major drains out falling into river Yamuna, extending sewerage network in all unauthorised colonies and JJ Clusters, regulation of Yamuna Flood Plain including removal of all encroachments / Dhobi Ghats, enforcement of Delhi Water Board Septage Management Regulations 2018, utilization of treated STP water and upgradation of 13 Common Effluent Treatment Plants treating industrial effluents, etc.

It was also decided by HLC to constitute a Committee under the Chairmanship of Divisional Commissioner, Revenue Department, GNCTD and consisting of CEO, DJB;

Commissioner MCD as members; and Secretary, Urban Development Department, GNCTD as member-cum-convenor of this Committee, to revisit the Delhi Water Board Septage Management Regulations 2018 to make them more effective & enforceable. The Committee will submit its report latest by February 15, 2023 to the Convenor of this HLC.

"Completion of construction of 40 New Decentralised STPs with total capacity of 92 MGD. 29 Decentralized STPs with total capacity of 57.57 MGD will be constructed by December, 2023. The remaining 11 Decentralized STPs having total capacity of 32.43 MGD, for which land is yet to



be allotted by DDA, required land will be made available at the earliest and thereafter construction will be completed within 12 months," it said.

It has been noted with concern that no desilting of existing drains network has

been carried out in the recent past. As a result most of the drains are either completely choked or functioning with 10-15% of their designed flow. Hence a major desilting drive must be undertaken. Out of an approximate 200 km of

trunk/peripheral sewerage held with DJB. 90.34 Km of desilting will be completed by June, 2023. In addition, fresh contract will be done for remaining 110 km at the earliest. The entire desilting will be completed by September 2023.

Out of 18 major drains out falling into river Yamuna in Delhi stretch, trapping of 11 drains which include Magazine Road, Sweeper Colony, Khyber Pass, Metcalf House, Tonga Stand, Moat (Vijay Ghat), Civil Military, drain 14, Tughlagabad, Kalkaji and Tehkhand has been completed.

DJB shall construct 10 MGD STP to trap the remaining flow in the Delhi Gate Drain within 12 months and

matter of allotment of land shall be resolved by all concerned by January 31. Sen Nursing Home Drain has been trapped into Sen Nursing Home STP as well as into the Ring Road trunk sewer. However, some marginal flow/overflow still passes during peak hours. DJB to take measures to stop this marginal flow by desilting the drain and proper operation of Ring Road trapping by March 2023.

74 un-trapped sub-drains [44 in Najafgarh Drain and 30 in Supplementary Drain (which is sub drain of Najafgarh drain)] to be intercepted by October 2023 while two un-trapped sub-drains of Shahdara Drain to be inter-

cepted by June, 2023. Full trapping and treatment of 242 MGD wastewater of the Interceptor Sewer Project (ISP) to be completed by DJB by June, 2023. "Work of sewer network is in Progress in 573 unauthorised colonies to be completed by Dec, 2023. Out of 161 unauthorized colonies, 123 awaiting NOC/Clearance from Forest, ASI and 0 Zone will be completed within 12 months of obtaining clearances but not later than June, 2024," it said.

The National Mission for Clean Ganga (NMCG) offered to develop a bio-diversity park in the Yamuna floodplain in case Delhi Development Authority (DDA) allots a land of appropriate area to it.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

NAME OF NEWSPAPERS_____

DA MONDAY, 30 JANUARY, 2023 | NEW DELHI

Senior citizens write to PM for setting up of CCTV surveillance & public toilets in area outside JNU

NEW DELHI: Protests at the Jawaharlal Nehru University (JNU) have started troubling senior citizens living in Delhi's Munirka Vihar, not for the noise or the traffic but strangers knocking on their doors to use the washrooms.

The lack of public convenience booths in the locality has also resulted in people relieving themselves in the open, causing a foul smell in the entire area, local residents said, claiming that they have approached authorities on several occasions but in vain.

The Senior Citizen Forum of the locality has now written to Prime Minister Narendra Modi highlighting the issue, demanding the construction of a public convenience booth to avoid open defecation on Bada Gang Nath Marg near Rock Garden, Munirka, and also the installation of CCTV cameras for security reasons.

In the letter dated December 12, 2022, the forum noted that the DDA flats in Munirka Vihar were mostly allotted to central government employees in 1977 and most of the residents now are senior citizens.

The situation worsens during protests at the university, which is located just opposite Munirka Vihar, locals claimed.

As there is no public convenience booth, police personnel and media persons stationed outside the university often knock on the doors of the people living there while some relieve themselves in the open, they alleged, adding that residents are also concerned about the health impact of the open defecation.

Speaking to PTI, forum member P N Malhotra said the concerns had been raised several times but nothing was ever done to address them.

Due to the lack of convenience booths, women police

Residents are also concerned about the health impact of the open defecation

personnel and media persons face major problems. "Men can relieve themselves in open. Let me stress that this is also wrong. But when there are no other option, they can. But women journalists stationed outside the university for hours have no option but to knock on our doors," he said.

"We try to help them, but we also feel unsafe because the security situation outside is not great. It is necessary to instal CCTV cameras in the area and build a convenience booth," Malhotra added.

Another resident, K C Pathak, also highlighted the issue and said a well-maintained

public convenience booth for police personnel and media persons needs to be built outside the JNU gate as the protest often continue for many days.

Besides, the facility will also come to the use of passersby as there is no other public convenience booth in the area, she said.

Protests at JNU and deployment of police personnel have become an usual phenomenon, causing inconvenience to residents of the locality, especially when traffic is diverted.

Stressing on the need for CCTV surveillance, resident Satwant Kaur said it was very much required as many residents in the area are senior citizens and some even live alone.

"Their houses are prone to theft and burglary," she said, adding, "CCTV surveillance would instill fear in the minds of outlaws."

In the letter to the prime

minister, the Senior Citizen Forum wrote, "Our police force in Delhi works day and night to safeguard the security of our worthy VIPs, senior citizens and residents of Delhi. Our police force deserves your appreciation and reward of encouragement to boost their efficiency."

The letter also mentioned other demands of the people in the locality such as covering open drains and verification of vendors. It asked for "installation of a small LED screen in the police booth near D Street gate of DDA flats, Munirka, and 85 CCTV cameras in D, E, F and G blocks."

There should be "verification of vendors, domestic helps, car cleaners etc. in our colony. Marking for parking of cars in our colony to provide way for ambulances and fire tenders. Construction of broken wall in D street," the forum said in the letter.

AGENCIES

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU

Sunday, January 29, 2023

DATED

Displaced, out of work, Kathputli Colony residents struggle to survive 5 years on

Muneef Khan
NEW DELHI

Five years have passed since Sheela Devi came from the now-demolished Kathputli Colony slum cluster to Sector G-7, Narela. Yet the 55-year-old struggles to make ends meet, as there aren't enough customers in the largely uninhabited housing colony to support her make-shift convenience shop.

"It's like a ghost town. There are hardly any people here, apart from us. In terms of public transport, just two DTC buses ply here. There are no employment opportunities nearby; my sons have to travel over 20 km to get work. We were happier in Kathputli Colony. Over here, we feel neglected and confined," said Ms. Devi, who spent 35 years living in the Kathputli Colony until it was demolished in late 2017.

In 2008, the Delhi Development Authority (DDA) selected Kathputli Colony, home to street performers and artisans, for an in-situ slum rehabilitation project executed on a public-private partnership (PPP) model by Raheja Developers. In line with the policy for



Ghost town: Heaps of garbage have taken over the DDA housing society in Narela with mostly uninhabited flats. SUSHIK KUMAR VERMA

rehabilitating the dwellers of J.J. Colony, the DDA relocated 2,800 Kathputli Colony residents to a transit camp at Anand Parbat, developed by the developers in 2013, till the completion of redevelopment work. The remaining 492 beneficiaries were allotted DDA flats in Narela.

For Sandeep, 29, the relocation resulted in him having to quit his job as a sweeper at a hospital close to the now-raised slum cluster, as he was unable to travel over 30 km daily.

Pointing towards heaps of garbage and sewage outside their housing society, Mr. Sandeep said that despite multiple complaints to

the authorities, the sanitation issues in the area have not been addressed.

"We moved here because we were told we would get a house in the redevelopment project. But five years have gone by and there is still no clarity on when the project will be completed," said Mr. Sandeep, who now takes up sanitation work within the area on a daily wage basis.

Shoaib, who heads a resident welfare association (RWA) for the slum-dwellers, feels the same. The 35-year-old said the condition of the flats has deteriorated due to the lack of maintenance.

Responding to these ob-

servations, the senior DDA official said, "it is the RWA's responsibility to maintain the space within their housing society". He added that close to 2,800 beneficiaries from the erstwhile slum cluster are eligible for a house at the project site. However, the process of allotment is yet to commence. "We cannot allow allotment of flats until we receive clearances from various agencies, including the Fire Department. It is the developer's responsibility to ensure all services are in place," said the senior DDA official.

Some residents fear the DDA may evict them since the agency hasn't released the final list of beneficiaries.

The senior DDA official clarified that the flats in Narela have not been given to the residents - of the now-raised Kathputli Colony - permanently. "Of these beneficiaries, if some are eligible for a home under the project and want to continue living in Narela, they will be permitted. However, if they are ineligible, they will have to vacate," said the official.

The DDA did not offer a comment on the issue.